



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

वर्ष 2020-2021 के लिए जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)
की अनुदानों की पूरक मांगें तथा वर्ष 2021-2022 का बजट

निर्मला सीतारामन
वित्त मंत्री
का
भाषण

Supplementary Demand for Grants of the Union Territory of Jammu & Kashmir
(with Legislature) for 2020-2021 and Budget for 2021-2022

SPEECH
OF
NIRMALA SITHARAMAN
MINISTER OF FINANCE

मार्च / March 17, 2021

वर्ष 2020-2021 के लिए जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)
की अनुदानों की पूरक मांगें तथा वर्ष 2021-2022 का बजट

निर्मला सीतारामन

वित्त मंत्री

का भाषण

अध्यक्ष महोदय,

1. सम्मानित सदन के माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि "जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019" के 31 अक्टूबर, 2019 से लागू होने से जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सृजन के पश्चात दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना सां.आ. 3937 (अ.) के द्वारा जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति शासन के अधीन बना हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किया जाता है।
2. जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सृजन से आशा और सकारात्मकता के युग का सूत्रपात हुआ है। जम्मू-कश्मीर के लोग आज भ्रष्टाचार और अलगाववाद से मुक्त भविष्य की ओर आशा से देख रहे हैं। अब हमारे पास एक राष्ट्र, एक संविधान और एक कानून है। सभी 890 केंद्रीय कानून अब जम्मू-कश्मीर पर लागू हो गए हैं। अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण कानूनों को हटा दिया गया है। 205 राज्य कानूनों को निरस्त कर दिया गया है और 129 कानूनों में बदलाव किया गया है। जम्मू-कश्मीर में सभी वर्ग के लोग न्याय और निष्पक्षता की उम्मीद कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति, अन्य पारंपरिक वनवासी, अनुसूचित जाति और सफाईकर्मियों जैसे कमजोर वर्गों के लोगों के अधिकार अब संबंधित अधिनियमों के लागू होने से सुनिश्चित किए जाते हैं। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार अब सुनिश्चित किए जा रहे हैं। एक न्यायसंगत और समतामूलक समाज बनाने के लिए, पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसी वंचित श्रेणियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए आरक्षण नियमों में संशोधन किया गया है। ओबीसी आरक्षण लाभ को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत और आय की सीमा 4.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। समाज के ऐसे वर्गों, जैसे पीओजेके और छम्ब के विस्थापित व्यक्तियों, पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों और सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों, जिनके साथ सदियों से भेदभाव किया गया है, को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया गया है। कश्मीरी प्रवासियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
3. निचले स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना:
हाल में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों में से एक 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना रहा है। पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में 74% से अधिक मतदान हुआ और 4103 सरपंचों और 28942 पंचों का चुनाव हुआ। खंड विकास परिषद (वीडीसी) के चुनाव में 98.3% मतदान हुआ और 276 वीडीसी अध्यक्ष चुने गए। जिला विकास परिषदों (डीडीसी) के चुनाव में 51.7% मतदान हुआ और 278 डीडीसी सदस्यों को चुना गया। डीडीसी चुनाव में

जम्मू-कश्मीर के लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी सकारात्मक बदलावों का संकेत है जो जम्मू-कश्मीर में आकार लेने लगी है।

4. शासन में बदलाव:

- (क) केंद्र शासित प्रदेश के सृजन के बाद से एक प्रमुख पहलू शासन का परिवर्तन रहा है जो पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह है। बैंक टू विलेज कार्यक्रम के तहत 4000 से अधिक अधिकारियों ने पंचायतों में दिन-रात दो दिन बिताए, जो शासन को लोगों की दहलीज पर लाने का एक प्रयास था। गांवों में मूलभूत व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम के तहत प्रत्येक पंचायत को 10 लाख रुपए प्रदान किए गए। बैंक टू विलेज कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 20,000 रुपए की लागत वाली खेल किट वितरित की गई और 20,000 युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक वित्त-पोषण प्रदान किया गया तथा 15,000 युवाओं को 241 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।
- (ख) शहरी क्षेत्रों में "मेरा शहर मेरा गौरव" नामक इसी तरह का एक जनपहुंच कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक नगरपालिका से कम से कम 10 युवक-युवतियों को चुना गया जिन्हें उद्यमी बनने के अवसर प्रदान किए गए हैं। इन कार्यक्रमों से लोगों का सशक्तिकरण हुआ है और एक उत्तरदायी प्रशासन का निर्माण हुआ है। इस अनूठी जन अभियान पहल ने अपार जवाबदेही लाने में मदद की है।
- (ग) यह खुशी की बात है कि जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश ने वित्तीय प्रबंधन में अभूतपूर्व स्तर की पारदर्शिता हासिल की है। बजट अनुमान, आबंटन और निगरानी प्रणाली (बीईएएमएस) को लागू किया गया है जिसके आधार पर अब निधियां ऑनलाइन और गतिविधि-वार जारी की जा रही हैं। विकास कार्यों और जांच में जनभागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए "सशक्तिकरण" वेब पोर्टल, जो बीईएएमएस का हिस्सा है, के माध्यम से सभी परियोजनाओं और संबंधित खर्चों का ब्यौरा पब्लिक डोमेन में डाला गया है। भुगतान के लिए जियो टैग लगी तस्वीरें डालना जरूरी हैं। ऑनलाइन बिलिंग के लिए जेके वेतन प्रणाली (JK Pay Sys) को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि बिना अपेक्षित प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन के या किसी ऐसे कार्य के बिना किसी भी कार्य के बदले कोई धनराशि वापस नहीं ली जा सकती, जहां निविदा आमंत्रित नहीं की गई है। सरकार के बजट के माध्यम से जो भी कार्य किए जा रहे हैं, अब एक-एक पैसे का हिसाब दिया जा रहा है और यह गर्व की बात है कि इस पारदर्शी तंत्र के कारण विकास की गति तेज हुई है। हमें केंद्र शासित प्रदेश को विकास का मॉडल बनाने का भरोसा है।
- (घ) हमारी सरकार महामारी के दौरान लोगों की जरूरतों का ध्यान रख रही है और आवामी मुलाकात और जनता दरबारों का नियमित आयोजन करके लोगों से जुड़ी हुई है। जन-भागीदारी का यह कार्यक्रम प्रखंड दिवस के रूप में लगातार जारी है और इस कार्यक्रम के तहत सरकार लोगों के द्वार पर पहुंच रही है।

5. विकास में तेजी:

- (क) 2018-19 के कैपेक्स बजट के तहत 8106 परियोजनाओं को पूरा किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान 10500 परियोजनाएं पूरी की गईं। इस वर्ष 16000 परियोजनाएं अर्थात् 2018-19 की संख्या से दोगुनी, पूरी होने जा रही है। इतना ही नहीं, महामारी की चुनौतियों के बावजूद परियोजना को पूरा करने की लागत में भी महत्वपूर्ण कमी आई है।

ख) अध्यक्ष महोदय, हम जम्मू-कश्मीर में विकास को तेजी से पटरी पर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक दिसंबर, 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। 8.45 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब काजीगुंड बनिहाल सुरंग पूरी होने वाली है। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगी कि 3500 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता तक पहुंचने के लिए हमें 70 साल लग गए हैं। लेकिन अब हमारे प्रयासों से 3300 मेगावाट और उत्पादन के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर ने सौभाग्य योजना के तहत शत प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण हासिल किया है और 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत 100 प्रतिशत पानी कनेक्शन प्राप्त किए जाने की उम्मीद है। यह हर गांव तक सड़क बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। चूंकि केंद्र शासित प्रदेश के सृजन से कई दशकों से लंबित परियोजनाएं पूरी हो रही हैं और इस वर्ष के समाप्त होने से पहले ऐसी एक हजार से अधिक परियोजनाओं के पूरा होने की उम्मीद है। जम्मू-कश्मीर सही मायनों में "सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास" मार्ग पर बढ़ रहा है।

6. अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन के प्रबंधन की दिशा में अग्रसर:

(क) आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत उठाए गए कदमों ने जम्मू-कश्मीर सरकार को महामारी से और उससे उत्पन्न आर्थिक मंदी से कारगर ढंग से निपटने में सक्षम बनाया है। यदि हम एसजीएसटी संग्रह को आर्थिक विकास के संकेत के तौर पर लें तो यह खुशी की बात है कि जम्मू-कश्मीर में एसजीएसटी संग्रह पिछले छह महीनों में 453 करोड़ रुपए है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 393 करोड़ रुपए था। पिछले छह महीनों में स्टांप ड्यूटी के औसत संग्रह में भी सकारात्मक वृद्धि का रुझान दिखा है। दिसंबर, 2020 में रिटर्न फाइल करने का प्रतिशत 86% के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 91% है। एमएसटी संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। पर्यटन क्षेत्र में भी पुनरुद्धार के संकेत दिखाई दिए हैं। सैलानियों के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि पर्यटन क्षेत्र ने देश-विदेश के सैलानियों को फिर से आकर्षित करना शुरू कर दिया है। अक्टूबर, 2020 में जम्मू में 1,88,702 आगंतुकों के मुकाबले जनवरी, 2021 में 7,29,175 पर्यटक आए। अक्टूबर, 2020 में 2697 आगंतुकों ने कश्मीर का दौरा किया और जनवरी, 2021 में 19102 ने कश्मीर की यात्रा की। कोविड-19 महामारी में छूट देने के बाद दिसंबर 2020 में कश्मीर में सबसे अधिक 13237 पर्यटकों की संख्या दर्ज की गई, जो पूरे वर्ष में कुल आगंतुकों का 39% है। इसके अलावा, इसी अवधि में 466246 तीर्थ यात्रियों ने जम्मू का दौरा किया।

(ख) अध्यक्ष महोदय, सरकार अर्थव्यवस्था में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने लंबे वर्षों की उथल-पुथल और महामारी से प्रभावित व्यापार क्षेत्र के राहत और पुनरुद्धार के लिए 1,350 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इसमें छह महीने के लिए सभी उधारकर्ताओं को ब्याज पर 5% की छूट, बिजली और पानी के शुल्क में 50% की छूट, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के लिए जेके बैंक द्वारा आवश्यकता अनुरूप 'हेल्प टूरिज्म' योजना, हाउसबोट में बायो डाइजेस्टर लगाने के लिए 80 प्रतिशत अर्थात् 1.80 करोड़ की सब्सिडी और 09 महीने के लिए हाउसबोटों/ टूरिस्ट गाइडों/ पिट्टु-वालों/ दांडी-वालों/ स्लेज-वालों/टडू और ऊंट-वालों में शिकारा-वालों/कामगारों को प्रतिमाह 1,000 रुपए का भुगतान शामिल है। डीबीटी मोड के माध्यम से वर्तमान महामारी के दौरान व्यापार पुनरुद्धार पैकेज के भाग के रूप में जम्मू-कश्मीर राहत कोष से पात्र लाभार्थियों को 8.17 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। सरकार ने वित्तीय समावेशन पर विशेष ध्यान दिया है जिससे बाजार में नकदी के प्रवाह में सुधार लाने में मदद मिली है। अब तक आर्थिक पैकेज के भाग के रूप में करीब 4 लाख

खाताधारकों को 500 करोड़ रुपए की ब्याज में छूट पहले ही दी जा चुकी है। जीईसीएल योजना के तहत 1,773 करोड़ रुपए के वितरण के लिए 64,000 कर्जदारों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, 11,000 फेरीवालों को पीएमएस वन निधि योजना के तहत 11 करोड़ रुपए की राशि के साथ कवर किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 9.80 लाख लाभार्थियों को 5,480 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।

- (ग) आत्म निर्भर भारत अभियान के साथ-साथ आर्थिक पैकेज को खूब सराहा गया है जिससे जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के मन में सकारात्मक भावना पैदा करने में मदद मिली है।
- (घ) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 10.20 लाख लाभार्थियों को पीएम किसान के तहत शामिल किया गया है और कुल 204 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किए गए हैं। 38,000 लाभार्थियों को मुद्रा (शिशु) ऋण के लिए 2% ब्याज अनुदान दिया गया है।

7. जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक विकास में तेजी:

- 7.1 28400 करोड़ रुपए के स्वीकृत परिव्यय से औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना की घोषणा से जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं पैदा हुई हैं। यह योजना अपेक्षाकृत दूरस्थ क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। नए निवेश को प्रोत्साहित करते हुए जम्मू-कश्मीर में मौजूदा उद्योगों को उचित सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार पैदा करना है जिससे क्षेत्र का प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक-आर्थिक विकास होता है। इसमें जम्मू-कश्मीर में विनिर्माण के साथ-साथ सेवा क्षेत्र इकाइयों के विकास की भी परिकल्पना की गई है। मुख्य प्रोत्साहन पूंजी निवेश प्रोत्साहन, पूंजीगत ब्याज अनुदान, जीएसटी संबद्ध प्रोत्साहन और कार्यशील पूंजीगत ब्याज प्रोत्साहन हैं। इस योजना को इस विजन के साथ लागू किया जा रहा है कि उद्योग और सेवा क्षेत्र से जम्मू-कश्मीर की आवश्यकताओं को पूरा करने पर नया बल मिलेगा और इससे 4.50 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा, तथा नए निवेश और मौजूदा निवेश को पोषित करके कौशल विकास और सतत विकास होगा। कहीं से भी निवेशक ऐसे प्रमोटरों को मालिकाना हक के हस्तांतरण पर किसी अनुचित प्रतिबंध के बिना निजी भूमि पर भी अपनी इकाइयां स्थापित कर सकते हैं। यह कदम जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास में एक मील का पत्थर है।
- 7.2 जम्मू-कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने और ऐसे निवेश के लिए ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने हेतु 14 (चौदह) क्षेत्रीय नीतियों की पहचान की है। क्षेत्र विशिष्ट नीतियों को पर्याप्त भूमि बैंक के साथ विधिवत समर्थन दिया जाएगा। हमारी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में निवेश करने के उद्देश्य से एक व्यवसाय शिखर सम्मेलन की तैयारी फिर से शुरू कर दी है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण बैठक का पिछला कार्यक्रम बदल गया था। अगले वित्त वर्ष के दौरान जम्मू-कश्मीर में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित होने की संभावना है। पहले इस शिखर सम्मेलन को पिछले वर्ष अप्रैल 2020 में आयोजित करने की योजना बनाई गई थी।
- 7.3 01.01.2020 से लखनपुर प्रवेश बिंदु पर टोल टैक्स को “एक राष्ट्र एक बाजार” की भावना से देश के अन्य क्षेत्रों के साथ जम्मू-कश्मीर के एकीकरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से समाप्त कर दिया गया है।

8. आर्थिक विकास:

सभी पहलों को आगे बढ़ाते हुए, हम 2021-22 में 7.5% की जीडीपी वृद्धि हासिल करने की उम्मीद करते हैं जो महामारी की स्थिति को देखते हुए हमारा वास्तविक मूल्य से कम अनुमान है।

9. बजट 2021-22:

9.1 जम्मू-कश्मीर के बजट 2021-22 में अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार, लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास, जम्मू-कश्मीर में बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के उद्देश्य से सुशासन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो हमारी प्राथमिकता है।

9.2 जम्मू-कश्मीर के लिए 2021-22 का बजट फिर से 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा, जो जम्मू-कश्मीर को विकास का मॉडल बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का सूचक है। वित्त वर्ष के लिए कुल बजट अनुमान 1,08,621 करोड़ रुपए का है, जिसमें से विकासात्मक व्यय 39,817 करोड़ रुपए है।

9.3 बजट के पूंजी घटक में काफी बढ़ोतरी हुई है। अपेक्षित राजस्व प्राप्तियां 97,141 करोड़ रुपए हैं जबकि राजस्व व्यय 68,804 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है जिससे पूंजीगत व्यय के लिए राजस्व अधिशेष 28,337 करोड़ रुपए हो जाएगा।

9.4 पूंजीगत आय का अनुमान 11,480 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय 39,817 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। 37 प्रतिशत निर्धारित बजट विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा।

10. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण:

हमने आधार सीडिंग के अलावा व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं के संबंध में डीबीटी के तहत अच्छी प्रगति हासिल की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 88 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 2,070 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं अन्य लाभार्थी योजनाओं के अंतर्गत शत प्रतिशत स्तर प्राप्त किया जा रहा है। हम विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत भी 100% कवरेज हासिल करना चाहते हैं।

11. सामाजिक-आर्थिक विकास:

11.1. स्वास्थ्य और आरोग्यता:

(क) जम्मू-कश्मीर सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखा है। 26 दिसंबर, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री ने एबी-पीएमजेवाई के साथ तालमेल करके एबी-पीएमजेवाई "सेहत" स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सभी 21 लाख परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए कवर किया जाता है। यह योजना सिर्फ जम्मू-कश्मीर के सरकारी और निजी अस्पतालों तक सीमित नहीं है। बल्कि देश में इस योजना के तहत पैनल में शामिल हजारों अस्पतालों से इलाज का लाभ उठाया जा सकता है। आयुष्मान भारत पीएमजेए के कवरेज का विस्तार सभी निवासियों को "ऐतिहासिक" और जम्मू-कश्मीर के लोगों की भलाई के बारे में सरकार के संकल्प का संकेत है।

- (ख) जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों, संबद्ध अस्पतालों और जिला अस्पतालों में 37 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि 227.73 करोड़ रुपए की लागत से कोविड-19 महामारी के कारण चिकित्सा ऑक्सीजन की अतिरिक्त आवश्यकता प्राप्त की जा सके। विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजना के माध्यम से स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 367.49 करोड़ रुपए की मशीनरी और उपकरण खरीदे जा रहे हैं। बेमिना, श्रीनगर में 116.25 करोड़ रुपए की लागत से 500 बिस्तरों का बाल चिकित्सालय स्थापित किया जा रहा है। लाल देड अस्पताल, श्रीनगर में 132.50 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड वाले अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 88.94 करोड़ रुपए की लागत से बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल, श्रीनगर में 06 बेड वाले आईसीयू सहित 120 बेड की विशेष आर्थोपेडिक यूनिट के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ऊधमपुर और हंदवाड़ा (जिला कुपवाड़ा) में 325 करोड़ रुपए की लागत से दो नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। दो नए एम्स अर्थात् जम्मू और कश्मीर में एक-एक एम्स का अगले वित्त वर्ष में निर्माण होने की भी उम्मीद है।
- (ग) हम श्रीनगर और जम्मू में 120 करोड़ रुपए की लागत से दो कैंसर संस्थान स्थापित करने जा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले भरदवाह, जम्मू-कश्मीर में "इंस्टीट्यूट ऑफ हाई आल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स" भी स्थापित किया जाएगा।
- (घ) अनंतनाग, बारामुला, सोपोर, गंग्याल और किश्तवाड़ में पांच नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज के स्तर तक 10 जीएनएम स्कूलों को प्रति कॉलेज 6 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उन्नत किया जा रहा है। कटुआ में 34 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक ड्रग जांच प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 में लगभग 1,456 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान 2020-21 की तुलना में 188 करोड़ रुपए अधिक है।

11.2 कृषि और बागवानी क्षेत्र:

- (क) जम्मू-कश्मीर को कृषि और बागवानी के क्षेत्र में अग्रणी बनने का ऐतिहासिक अवसर मिला है। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का हर संभव प्रयास कर रही है और पारंपरिक कृषि और बागवानी दोनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नैफेड के सहयोग से अगले पांच वर्षों में सेब, अखरोट, चेरी, विदेशी सब्जी और अन्य बागवानी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कटुआ, उत्तरी कश्मीर और दक्षिण कश्मीर में तीन कोल्ड स्टोरेज क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। हमारा लक्ष्य लगभग 5500 हेक्टेयर भूमि पर बागवानी फसलों का उच्च घनत्व वृक्षारोपण प्राप्त करना है जिससे किसान भाइयों की आय में 3 से 4 गुना तक वृद्धि होगी। 2021-22 में 120 हेक्टेयर क्षेत्र का उच्च घनत्व वाले वृक्षारोप के तहत विस्तार किया जाएगा।
- (ख) हम बागवानी और फसल के बाद प्रबंधन में ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के अवसरों के लिए हर संभव सहयोग देंगे। वर्ष 2021-22 में अगले तीन वर्षों में सीए भंडारण की 4 एलएमटी क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ सीए भंडार स्थापित करने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी/ सहायता के रूप में 74.55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

- (ग) वर्ष 2021-22 के दौरान 7.50 लाख किसानों को 15.50 करोड़ रुपए के निवेश से एक लाख क्विंटल बीज वितरित करके लाभ दिया जाएगा। 2021-22 के दौरान 91.27 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ 2500 पंप सेटों, 750 बोर कुओं और बहुत से क्षेत्रीय नहरों के निर्माण जैसी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराकर 87750 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करके 25000 किसानों को लाभ दिया जाएगा। वर्ष 2021-22 में 65.81 करोड़ रुपये का प्रावधान करके कृषि उपकरणों को उपलब्ध कराकर 30000 किसानों को लाभ पहुँचाना है। एक करोड़ रुपये का प्रावधान करके दो मंडियों की स्थापना किया जाना है जिससे 25000 किसानों को लाभ पहुँचेगा। क्षमता निर्माण के क्षेत्र में 35000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना है जिसके लिए 26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- (घ) किसान कृषि विश्वविद्यालयों के एग्रेडिशन संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें इसके लिए जर्मप्लाज्म उत्पादन जैसे सूचकांकों के माध्यम से उनको शसक्त बनाया जा रहा है जिसके लिए 2.50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
- (ङ) सुनिश्चित सिंचाई सुविधा के साथ केसर फसल का उत्पादन आगे बढ़ने की उम्मीद है।
- (च) विश्वसनीय सिंचाई सुविधा का विस्तार करके केसर फसल के उत्पादन में और अधिक बढ़ोतरी किये जाने की आशा की जा रही है। 700 हेक्टेयर को कवर करके सहतूत की खेती में बढ़ोतरी किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए 0.75 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है।
- (छ) गुणवत्ताप्रद शिल्कवार सीड के विकास और उत्पादन/वितरण का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही इसको अवसंरचनापरक समर्थन भी दिया जाना है। इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में 7.25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जा रहा है।
- (ज) वर्ष 2021-22 में 22.30 लाख मिट्रिक टन शुष्क और ताजे फलों का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है (22 मिट्रिक टन ताजे फल और 0.30 मिट्रिक टन शुष्क फल)।

कृषि और बागवानी क्षेत्रों के लिए वर्ष 2021-22 में लगभग 2,008 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष बजट आबंटन से 695 करोड़ रुपये से अधिक है।

11.3 पशु भेड़ पालन और मात्सिकी क्षेत्र:

- (क) अगले वर्ष हम 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने वाले हैं जो कि सैकड़ों लोगों को दिये गये प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा होगा। इसके लिए एक समेकित भेड़ विकास योजना लागू की जाएगी जिसमें 2000 इकाईयों की स्थापना होगी। जिससे 27500 भेड़ों/बकरियों को इसमें लाया जाएगा और 5 लाख किलोग्राम मांस का अतिरिक्त उत्पादन होगा। मेंढों/बक्स जिनकी संख्या वर्तमान में 5000 है, में 4000 अतिरिक्त मेंढों/बक्स को शामिल किया जाएगा जिससे प्रति पशु चमड़े का उत्पादन 18 किलोग्राम से बढ़ाकर 21 किलोग्राम और ऊन का उत्पादन 2 किलोग्राम से बढ़कर 2.5 किलोग्राम हो जाएगा। मिल्क पूल में 20000 मवेशियों को शामिल किया जाएगा और इस तरह से समेकित डेरी विकास योजना पूरी क्षमता से क्रियान्वित किया जाएगा जिससे डेरी क्षेत्र में रोजगार के मामले में काफी सुधार आएगा।

- (ख) सचल पशु चिकित्सालय को चालू किया जाएगा जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रगतिशील पशु पालकों को उनके दरवाजे पर पशु स्वास्थ्य सेवा/प्रजनन सेवाएं सुलभ हो सकें।
- (ग) जम्मू व कश्मीर कुकुर नीति 2020 और कुकुर विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कुकुर मांस उत्पादन में, जो वर्तमान 7.8 करोड़ किलोग्राम है, बढ़कर 8.5 करोड़ किलोग्राम तक हो जाएगा और इसमें 30,000 लोगों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ हो सकेंगे।
- (घ) सरकार विभिन्न योजनाओं को लागू करके वर्तमान के 21000 मिट्रिक टन मत्स्य उत्पादन में 1000 मिट्रिक टन और बढ़ोतरी करने के प्रयास कर रही है। इसके लिए विपणन प्लेटफार्म को सशक्त बनाया जा रहा है और देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्राऊट को भेजने का प्रावधान रखा जा रहा है। संघ राज्य क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए “रि-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लोक टेक्नॉलोजी” नामक एक नये हस्तक्षेप को लागू किया जा रहा है। नयी हेचरियों की स्थापना की जा रही है और वर्तमान हेचरियों में सुधार किया जा रहा है और इसमें बहुस्तरीय प्रणाली को लागू किया जा रहा है जिससे कि इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए और साथ ही साथ निर्यात की दृष्टि से भी इसके बीज के उत्पादन को भी बढ़ाया जा सके।

वर्ष 2021-22 में पशु, भेड़ पालन और मत्स्य क्षेत्र के लिए लगभग 338 करोड़ रुपये के आबंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष के भजट आबंटन से 36 करोड़ रूपया अधिक है।

11.4 ग्रामीण अर्थव्यवस्था:

- (क) प्रधान मंत्री आवास योजना- वर्ष 2021-22 के दौरान 1,17,419 मकानों को बनाए जाने का हमारा लक्ष्य है जिससे की ऐसे पात्र ग्रामीण परिवारों को, जो कि कच्चे और जर्जर मकानों में रह रहे हैं, पक्के मकान उपलब्ध करा सकें।
- (ख) हिमायत (डी डी यू- जी के वाई) योजना के अंतर्गत 39113 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और 2021-22 के दौरान 209112 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रकार की नौकरी दिये जाने की आशा है।
- (ग) वर्ष 2021-22 में ही 16000 स्वसहायक दलों (एसएचजी) और 1600 ग्राम स्तरीय संगठनों की स्थापना की जायेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 24866 स्वसहायक दलों को रिवाल्विंग फंड और 46799 स्वसहायक दलों को कम्प्यूनिटी इनवेस्टमेंट फंड प्रदान किया जाएगा।
- (घ) जहां तक विकास की बात है, 2021-22 में हम 130 रूरल कनेक्टिविटी वर्क्स का काम पूरा कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है।
- (ङ) गुड गवर्नेंस को दरवाजे-दरवाजे तक पहुँचाने के लिये चुने गए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना जरूरी है। 700 चयनित प्रतिनिधियों को अन्य राज्यों में एक्सपोजर कम ट्रेनिंग विजिट पर भेजने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2021-22 में 276 बी डी सी अध्यक्षों, सभी डी डी सी सदस्यों, 4291 सरपंचों और 40,000 पंचों को प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा 100 नए पंचायत घर बनाए जाएँगे।

- (च) मोबाइल के प्रयोग के माध्यम से, मनरेगा में काम कर रहे लोगों का मौके पर ही पता लगाने के लिए एक मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा।
- (छ) मनरेगा के अंतर्गत 0.60 लाख लोग कार्य किये जाएंगे जिनमें से 30% कार्य जल संरक्षण के होंगे 30% लोगों को लाभ देने के लिए होंगे और इसके अलावा 3.50 करोड़ कार्य दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 4,817 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष के बजट आबंटन से 342 करोड़ रुपये अधिक है।

11.5 विद्युत क्षेत्र:

- (क) आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, जम्मू-कश्मीर विद्युत निगम को क्रायशील बनाने के लिए हमारी सरकार ने 11,025 करोड़ रुपये की पिछली देयता को अनापत्ती दे दी है इससे यह विभाग अपने देयता के भार से मुक्त हो जाएगा और साथ उसको ब्याज से भी मुक्ति मिल जाएगी और उसे एक ऐसी सहायक कंपनी के रूप कार्य करने के लिए जीवनदान मिल जाएगा जिसका गठन विद्युत विभाग को अलग करके किया गया है।
- (ख) किस्थाई-II (930 एमडब्ल्यू), सवालाकोट (1856 एमडब्ल्यू), ऊरी-I स्टेज- II (240 एमडब्ल्यू), और दुलहस्ती स्टेज-II (258 एमडब्ल्यू) जैसी नयी जल विद्युत परियोजनाओं को क्लीयर करने की सभी अड़चने दूर हो गयी हैं और 850 मेगावाट की नयी संयुक्त रैटल परियोजना की क्रियाविधि को अंतिम रूप दे दिया है।
- (ग) पीएमडीपी के अंतर्गत दो लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जो कि शहरी उपभोगताओं के लिए हैं और यह काम जून 2021 तक पूरा हो जाना है जिससे संग्रह क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी।
- (घ) इस कड़ाके की सर्दी वाले मौसम में भी ट्रांसफार्मरों को जो नुकसान होता था वह, विशेष रूप से कश्मीर में, बहुत हद तक कम हो गया है। इन ट्रांसफार्मरों को आगे कोई क्षति न होने पाए इसके लिए 2021-22 के दौरान सभी फीडरों में ट्रांसफार्मर कटआऊट्स लगाए जाएंगे।
- (ङ) शिकायतों के समाधान के लिए 24x7 ई-कस्टमर केयर/कॉल सेंटर भी स्थापित किये जाएंगे।
- (च) अक्टूबर, 2022 तक 22 ऐसी परियोजनाएं पूरी कर ली जाएंगी जिनका उद्देश्य ग्रिड स्तर पर ट्रांसफार्मर की क्षमता को बढ़ाना है।
- (छ) इस संघ राज्या क्षेत्रभर में सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे जिससे कि नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके और इस तरह के सोलर प्लांट लगाने के पंपोर, कालाकोटे और कावा में जगह का पता लगा लिया गया है।
- (ज) सक्षम और विश्वसनीय माध्यम के लिए पीजीसीआईएल ने पीएमआरपी योजना के अंतर्गत एक ऑप्टिकल ग्राऊन्डेड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) परियोजना की स्थापना कर रहा है जो जल्दी ही पूरा होने वाला है। जिसका

उद्देश्य इस पूरे संघ राज्य क्षेत्र में 220 केवी और 132 केवी ग्रिड स्टेशनों के बीच विश्वसनीय और सक्षम संचार व्यवस्था स्थापित करना है।

वर्ष 2021-22 में विद्युत क्षेत्र के लिए लगभग 2,728 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष के बजट आबंटन से 119 करोड़ रुपये अधिक है।

11.6 पर्यटन और संस्कृति:

(क) कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र को पुनः जागृत करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करके और इसके लिए पूरे जोश से अभियान चला कर पर्यटन को बढ़ावा देने का हर प्रयास करेगी। सरकारी और निजी निवेश के माध्यम से पर्यावरण के नये स्थलों का पता लगाया जाएगा। सहासिक पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जल आधारित पर्यावरण क्रियाकलापों को प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करके गोल्फ टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सड़कों के किनारे विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएंगी और सभी जगह के पर्यावरण से संबंधित सभी परिसंतियों का नवीनीकरण किया जाएगा और उनका उन्नयन भी किया जाएगा जिससे कि अच्छे-से-अच्छे पर्यटन यहां के लिए आकर्षित हो सकें।

(ख) इस वर्ष जून/जुलाई में प्रारम्भ होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा को सहज रूप से संचालित करने के लिए हम विशेष ध्यान दे रहे हैं जिससे तीर्थ यात्री इस पवित्र गुफा का दर्शन कर सकें और यहां यथोचित सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जा सकें। हम विरासत वाले स्थलों के रख-रखाव और संरक्षण पर भी ध्यान दे रहें हैं। पिछले वर्ष हमने 3 धार्मिक परिक्रमाओं की घोषणा की थी जिसमें एक सूफी परिक्रमा भी शामिल है जिसका जम्मू-कश्मीर सरकार के द्वारा विकास किया जा रहा है।

(ग) जम्मू-कश्मीर सरकार अपने समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन को भी बढ़ावा देगी। इस बारे में पर्व संबंधी क्रियाकलापों के अलावा स्थानीय फिल्म/सिनेमा/थियेटर को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

वर्ष 2021-22 में पर्यावरण और संस्कृति क्षेत्रों के लिए लगभग 786 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष 509 करोड़ रुपये अधिक है।

11.7 जनशक्ति विभाग:

I. पीएचई क्षेत्र:

(क) जम्मू और कश्मीर जल संसाधन से भरपूर हैं। हम जनजीवन मिशन (जेजेएम) के तहत सितम्बर, 2022 तक जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक ग्रामीण घरों को 100% पाइप जल से जोड़ने का लक्ष्य रखते हैं। श्रीनगर और गंदेशबल दो जिलों में पहले ही यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और 9 जिलों में मार्च, 2022 तक और शेष 7 जिलों में सितम्बर, 2022 तक यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत, वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 3.83 लाख पानी के कनेक्शन लगाए गए हैं जिससे 19.65 लाख जनसंख्या लाभान्वित हुई है। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी बचे हुए स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी पानी का कनेक्शन दिया जाएगा।

(ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 410 जल आपूर्ति योजना पूर्ण कर ली गयी हैं।

II. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र:

- (क) वर्ष 2021-22 के दौरान एआईबीपी-पीएमकेएसवाई के तहत चल रही 57 छोटी सिंचाई योजनाओं को पूर्ण कर लिया जाएगा और कुल 0.19 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता को प्राप्त कर लिया जाएगा।
- (ख) वर्ष 2014 की भयंकर बाढ़ अभी भी हमें याद है और एक “झेलम नदी और इसकी सहायक नदियों के लिए व्यापक बाढ़ प्रबंधन योजना” में यह लक्ष्य रखा गया था कि संगम बिन्दु पर झेलम नदी से कुल 41,000 क्यूसेक्स को बढ़ाकर 60,000 क्यूसेक्स और पादशाही बाघ, श्रीनगर में 8700 क्यूसेक्स से 17,000 क्यूसेक्स की क्षमता को बढ़ाने की गति दी जाएगी। ताबी बैरेज (बैलेस पोर्सन) और उझ बहु-उद्देश्य परियोजना (यूएमपीपी) पर भी कार्य शुरू किया जा चुका है।

वर्ष 2021-22 में जल शक्ति विभाग के लिए लगभग 6,346 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष 5,102 करोड़ रुपये अधिक है।

11.8 आवासीय और शहरी विकास क्षेत्र:

- (क) अटल मिशन फोर रिजुवनेशन एन्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमरुत) के तहत, आगामी वित्तीय वर्ष में 7 परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा जिनमें पंजतीर्था बहुस्तरीय पार्किंग, और जम्मू में ताबी नदी पर 5 नालों का मल प्रबंधन, श्रीनगर में साइकिल ट्रैक, त्रिकुटा नगर में जल निकासी, श्रीनगर में बहुस्तरीय पार्किंग, प्रज्ञ ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस), श्रीनगर चरण-II और जल आपूर्ति योजना, रंगिल।
- (ख) स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान, समेकन/पीपीपी के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की 40 परियोजनाओं के पूर्ण होने की संभावना है। इसका मुख्य लक्ष्य वाई-फाई सुविधाओं को प्रदान करना, स्मार्ट हेल्थ केन्द्रों, ऐतिहासिक बाजारों का उन्नयन, रिवर वैंडिंग मशीनों को लगाना, स्मार्ट क्लास रूम, विद्युत चालित वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन, नदी के किनारों का प्रदीपन, साइकिल ट्रैक/हॉकर क्षेत्रों का विकास, फ्लाई ओवर के नीचे पार्किंग और खाली क्षेत्र का विकास करके लोगों के जीवन में सुधार करना है।
- (ग) स्वच्छ भारत मिशन (श) और कचरा प्रबंधन के तहत 74 एमएलडी क्षमता के साथ 16 नये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे जिससे लगभग 2 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। कुल 25 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीएस) का ओडीएफ + श्रेणी को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- (घ) सभी 78 यूएलबीएस में 100% एलईडी स्ट्रीट लाइटों को लगाया जाना सुनिश्चित किया गया है।
- (ङ) हमारा यह प्रयास होगा कि स्रोत में ही 100% कचरे को अलग कर लिया जाए और घर-घर जाकर कचरे का संग्रहण किया जाए। हम श्रीनगर और जम्मू में एसडब्ल्यूएण संयंत्र लगाएंगे जिससे प्रतिदिन लगभग 850 मिट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन किया जाएगा। हम 76 यूएलबीएस में 690 मिट्रिक टन कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए कचरा प्रबंधन की केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाईयां लगाएंगे।
- (च) एनजीटी के निर्देश पर सीपीसीबी के द्वारा 09 चिन्हित प्रदूषित नदी क्षेत्र का उद्धार किया गया है और पुरुद्धरण के लिए वर्ष 2021-22 के लिए कुल 200 करोड़ रुपये रखे गये हैं। हाऊस वोट में हल बेस्ड बाँयो डायजेस्टर लगाए जाएंगे, एरेटर्स भी लगाए जाएंगे और डी-वीडिंग मशीन खरीदी जाएगी।

(छ) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कुल 25000 घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। सही लाभार्थियों की पहचान जिन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाना है उनके लिए वर्ष 2021-22 में 50,000 लाभार्थी घरों को जियो-टैग किया जाएगा।

वर्ष 2021-22 में आवासीय और शहरी विकास क्षेत्र के लिए लगभग 2,710 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष 1,432 करोड़ रुपये अधिक है।

11.9 शिक्षा क्षेत्र- मानव पूंजी का निर्माण:

- (क) वर्ष 2021-22 में जम्मू-कश्मीर में सकल नामांकन अनुपात (ग्रॉस एनरॉलमेंट रेशियो) का लक्ष्य प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी के स्तर पर जो इस समय क्रमशः 83.38, 72.77, 67.76 और 53.70 है उसे बढ़ाकर क्रमशः 85.00, 74.00, 69.50 और 57.00 करना है। जम्मू और कश्मीर में स्कूल छोड़ने वालों की दर जो कि हाई स्कूल के स्तर पर 17.12 है उसे मार्च, 2022 तक कम करके 15.00 तक ले आना है। बराबर-बराबर की संख्या में सेकेन्डरी और सीनियर सेकेन्डरी स्कूलों में 723 आईसीटी लैब्स स्थापित की जा रही हैं जिनके लिए 46.27 करोड़ रुपये का खर्च रखा गया है। 38 महिला छात्रावासों का काम पूरा हो गया है जिनपर 114.14 करोड़ रुपये का खर्च आया है। 40 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीडीबी) के भवन का काम पूरा होने वाला है जिनपर 43.33 करोड़ रुपये का खर्च आने वाला है।
- (ख) वर्ष 2021-22 में 245 निर्माण कार्यों को पूरा किया जाना है जिसमें मॉडल स्कूलों की स्थापना, अतिरिक्त कक्षाओं के कमरों के निर्माण, प्रशासन सुविधाओं, स्मार्ट क्लास रूम का निर्माण आता है। 10 डिग्री कालेज भवनों को पूरा किया जाएगा जो कि बनिहाल, कुपवाड़ा, खिलोतरन, माहौर, कालाकोटे, हाडीपोरा, सिंगपोरा (पट्टन), विलगाम (कुपवाड़ा) और पड्डार (किस्तवार) में पढ़ेंगे और वर्तमान डिग्री कालेजों में कक्षाओं के लिए 108 अतिरिक्त कमरे बनाए जाएंगे।
- (ग) 10 कालेजों में मॉडर्न साइंस लेबोरेटरी ब्लॉक्स बनाए जाएंगे।
- (घ) 1200 अतिरिक्त कक्षाओं के कमरों को आईटी युक्त बनाया जाएगा। बाकी सभी डिग्री कालेजों में पुस्तकालयों का ऑटोमेशन किया जाएगा।
- (ङ) सभी डिग्री कालेजों में स्टूडेंट स्किल सेन्टर बनाए जाएंगे। स्किल इन्हेंसमेंट ट्रेनिंग (एसईटी) स्कीम के अंतर्गत 10,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बराबर-बराबर की सं. में प्राथमिक स्कूलों में 382 कम्प्यूटर एडेड लर्निंग सेन्टर्स बनाए जाएंगे जिनपर 19.10 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। बराबर-बराबर की संख्या में हाई/हायर सेकेन्डरी स्कूलों में 77 व्यवसायिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी जिनपर 3.85 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

वर्ष 2021-22 में स्कूल और हायर एजुकेशन सेक्टर के 1,873 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष के बजट आबंटन से 523 करोड़ रुपये अधिक है।

11.10 सड़क संपर्क:

- (क) जम्मू-कश्मीर सरकार ने 01 अप्रैल, 2021 से ऑनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम (जेकेपीडब्ल्यूडीओएमएएस) लागू करने पर विचार कर रही है जिससे डीपीआर की तैयारी से लेकर फाइनल बिल के पेमेंट तक की सभी कार्यवाही ऑनलाइन मोड में की जाएगी।

- (ख) सड़कों एवं पुलों के बेहतर जीवकाल एवं टिकाऊपन के लिए गुणवत्ता जांच पर जोर देना अनिवार्य है। तदनुसार, प्रत्येक जिले में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है।
- (ग) निगरानी की प्रक्रिया तैयार करने और तीसरी पार्टी निरीक्षण प्रणाली आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के परामर्शदाता नियुक्त किए जाएंगे।
- (घ) पीएमजीएसवाई I और II के अंतर्गत, 2021-22 के दौरान 4500 किमी. की सड़क लम्बाई पूरा करने का हमारा प्रयास होगा। हमारा प्रस्ताव 150 नए गांवों को जोड़ना है। जम्मू एवं कश्मीर पीएमजीएसवाई III में शामिल होगा जिसके लिए 2021-22 में अपग्रेड करने के लिए 1750 किमी लम्बाई की सड़क को स्वीकृत किया जा रहा है। 2021-22 तक जम्मू एवं कश्मीर में 100% सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए पीएमजीएसवाई IV के अंतर्गत 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक व्यक्तियों वाले गांवों को जोड़ने के लिए कोर नेटवर्क का लक्ष्य है।
- (ङ) नगरों एवं शहरों/पीएमजीएसवाई/सीआरआईएफ/नाबार्ड के अंतर्गत 2021-22 के दौरान कुल 8000 किलोमीटर सड़कों का ब्लैक टोपिंग करने का लक्ष्य है।
- (च) 2021-22 में 14 पुलों को पूरा करने का लक्ष्य है जिसका 2.85 लाख जनसंख्या को लाभ मिलेगा।
- (छ) संपूर्ण जम्मू एवं कश्मीर में गड्ढा मुक्त सड़क सुनिश्चित करने के लिए 100 करोड़ रुपए पहले ही मुहैया कराए गए हैं और 2021-22 में 150 करोड़ रुपए मुहैया कराए जा रहे हैं।

सड़क और पुल क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 4,089 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आबंटन से 467 करोड़ रुपए अधिक है।

11.11 उद्योग एवं वाणिज्य:

- (क) जैसाकि पहले ही बताया गया है, जम्मू एवं कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की नई योजना के अलावा, केन्द्र शासित प्रदेश में नई औद्योगिक संपदाओं के विकास के लिए 2021-22 में 200 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। सरकार 50 करोड़ के परिव्यय से व्यापार केन्द्र स्थापित करेगी। जम्मू क्षेत्र में मीन चरखा (सम्बा), करंडी, मीर्थ घाटी और शहर लॉगेट (कथुआ) में नई औद्योगिक संपदाओं के विकास के लिए 44.80 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
- (ख) 2021-22 के दौरान कुड के निकट संग्योट, पहलीपोरा (लार) और चिवा (बांदीपोरा) में फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे।
- (ग) कचरे के सही ढंग से निपटान के लिए, 20.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में तीन सामान्य उत्प्रवाही जलशोधन संयंत्रों (सीईटीपी) का निर्माण किया जाना है।

- (घ) 100 करोड़ रुपए की लागत पर 2021-22 के दौरान दो आईटी टावर्स, एक जम्मू में और दूसरा श्रीनगर राजधानी नगरों प्रत्येक में पूरे किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, 2021-22 में सभी जिला मुख्यालों में ग्रामीण बीपीओ स्थापित किए जाने की संभावना है।
- (ङ) जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जिसमें 2021-22 के लिए 25 करोड़ रुपए की मार्जिन राशि शामिल है, के अंतर्गत 1231 यूनिटों में 7386 व्यक्तियों को रोजगार का अवसर प्राप्त होने की आशा है।
- (च) मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 456 निवेश प्रस्ताव/समझौता ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें जम्मू एवं कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में 23,000 करोड़ रुपए का निवेश निहित है जहां निवेशकों ने निवेश करने की गहरी इच्छा दर्शायी है। जम्मू एवं कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय रोड शो सहित जम्मू एवं कश्मीर वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- (छ) क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 2000 सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जाएगा जिससे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से 12000 लोगों को लाभ मिलेगा। शिल्पकार क्रेडिट कार्ड योजना (एसीसी) के अंतर्गत शिल्पकारों द्वारा 2 लाख रुपए तक ऋण प्राप्त करने के लिए शिल्पकारों को 7% की ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।

वर्ष 2021-22 के लिए उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के लिए लगभग 648 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आबंटन से 291 करोड़ रुपए अधिक है।

12. सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र :

- (क) 2021-22 में बाल आश्रम, नारी निकेतन भवनों और हाफ वे होम्स के निर्माण का प्रस्ताव है।
- (ख) आंगनबाड़ी केन्द्रों में डे केयर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और एकीकृत बाल विकास योजना की वास्तविक समय में निगरानी और रिकॉर्ड अनुसंधान के साथ एडब्ल्यूसी के मौजूदा कार्यप्रणाली को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने के लिए सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर (सीएएस) आरंभ किया जाएगा।
- (ग) 55 व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं के तहत 100% बीमाकृत राशि सुनिश्चित की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष जोर दिया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजना के अंतर्गत 59% वृद्धि दर्ज की गई है जिनमें कुल मिलाकर 742781 लाभार्थी शामिल हैं।
- (घ) गुज्जर एवं बेकरवाल छात्रों तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को डीबीटी विधि से 100% भुगतान के साथ माध्यमिक पूर्व और माध्यमिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 100% छात्रवृत्ति सुनिश्चित की जा रही है। अनुसूचित जाति माध्यमिकपूर्व छात्रवृत्ति के अंतर्गत 1091 से बढ़कर 2136 छात्र अर्थात् 100% का उछाल और माध्यमिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत 26032 से बढ़कर 59112 अर्थात् 127% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- (ङ) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिए, गुज्जरों/बकरवालों के लिए दुग्ध ग्रामों, पुस्तकालयों को स्थापित करके क्लस्टर ट्राइबल गावों का विकास किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के अलावा, गुज्जर, बकरवाल और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाएं तैयार की जाएंगी।

वर्ष 2021-22 के लिए सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 174 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जो पिछले बजट के आबंटन से 59 करोड़ रुपए अधिक है।

13. कश्मीरी प्रवासियों को राहत एवं पुनर्वासन:

I. पारगमन आवास:

पीएम पैकेज के अंतर्गत 6000 आवासों में से 1025 पारगमन आवास पहले ही पूरे कर दिए गए हैं। पारगमन आवासों के 1488 आवासों पर कार्य 2021-22 में आरंभ किया जा रहा है, इसके अलावा अन्य 2444 आवासों के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है।

II. रोजगार:

पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी प्रवासियों के लिए तैयार 6000 पदों में से 3841 पद भर दिए गए हैं और शेष पदों के लिए भर्ती की जा रही है।

III. अन्य घटक:

पीएम पैकेज के अन्य घटक जैसे कि आवासन, रोजगार, ऋण पर छूट, नकद सहायता और निशुल्क राशन 2021-22 में जारी रहेंगे।

उपर्युक्त पैकेज के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 846 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

14. युवा सशक्तिकरण, रोजगार एवं उद्यमशीलता:

- (क) रोबोटिक्स, डिजाइन इंजीनियरिंग, विद्युत वाहन अनुरक्षण एवं मरम्मत, इंटरनेट आफ थिंग्स, मेकाट्रोनिक्स तथा अन्य कई ट्रेडों जैसे उद्योग संबंध पाठ्यक्रमों में तकनीकी संस्थाओं के छात्रों का कौशल बढ़ाने के लिए राजकीय पोलिटेक्नीक जम्मू एवं राजकीय पोलिटेक्नीक बारामुला में टाटा टेक्नोलोजीज के सहयोग से अनुसंधान, अभिनविनता, उष्णायन और प्रशिक्षण (सीआईआईआईटी) के दो केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।
- (ख) युवाओं के उत्थान एवं रोजगार के लिए "मिशन यूथ" के माध्यम से युवा रोजगार जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल के लिए 2021-22 के दौरान 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- (ग) सरकार जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रमों तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से स्वरोजगार के अलावा विभिन्न बैंक प्रायोजित योजनाओं एवं यूथ स्टार्ट अप योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार शुरू करने के लिए युवाओं को सभी संभव वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।
- (घ) निजी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में युवाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए जॉब पोर्टल बनाया जाएगा और रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। विदेशों में नौकरी प्राप्त करने में युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी रोजगार निगम का भी नवीकरण किया जाएगा।

- (ड) स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 2000 बेरोजगार युवाओं को शामिल किया जाएगा और लगभग 5000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें विभिन्न कार्यों/क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाया जा सके।
- (च) अध्यक्ष महोदय, मैं यहां बताना चाहती हूँ कि भर्ती अभियान में तेजी लाने के लिए 10000 वर्ग घ रक्तियों के अलावा 12379 राजपत्रित एवं अराजपत्रित रक्तियों की पहचान की गई है।

15. खेलकूद गतिविधियां:

युवाओं को खेलकूद गतिविधियों में प्रवृत्त करने के लिए सरकार 04 प्रतिस्पर्धाओं यथा फूटबॉल, कबड्डी, वॉलीबाल और हॉकी में प्रीमियर लीग आयोजित करेगी जिसमें 8500 सहभागियों के शामिल होने की आशा है। हम खेलकूद गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रत्येक इच्छुक युवा को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू एवं कश्मीर के लोग क्रिकेट में गहरी रूचि दिखा रहे हैं। क्रिकेट के खिलाड़ियों को समुचित कोचिंग में लाने और उन्हें बेहतर तकनीक से अवगत कराने के लिए, केन्द्र शासित प्रदेश के उभरते क्रिकेटरों को प्रशिक्षण देने के लिए श्री सुरेश रैना एकेडमी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। हाल ही में "गुलमर्ग" में खेलो इण्डिया कार्यक्रम के अंतर्गत शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया था जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी दिखाई। बड़ी संख्या में भागीदारी करने के लिए शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा जिससे पर्यटन क्षेत्र में भी तेजी आएगी।

युवा सशक्तिकरण, रोजगार, उद्यमिता एवं खेलकूद गतिविधियों के लिए, वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 513 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आबंटन से 17 करोड़ रुपए अधिक है।

16. पर्यावरण:

2021-22 के दौरान लगभग एक करोड़ पेड़ लगाकर हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए बड़े पैमाने पर वनारोपण अभियान चलाया जाएगा। वूलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इस झील को बचाने के लिए इस झील की जलभरण क्षमता बढ़ाने के लिए "वूलर झील संरक्षण एवं प्रबंधन" कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसे बाढ़ शमन पहल के रूप में 200 करोड़ रुपए की लागत पर 2021-22 में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, वूलर झील को अतिक्रमण से बचाने के लिए इसके चारों ओर सर्कुलर सड़क का निर्माण करने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जम्मू में अत्याधुनिक जम्बों चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है।

वन, पर्यावरण एवं वातावरण के लिए वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 218 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट आबंटन की तुलना में 3 करोड़ रुपए अधिक है।

17. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी:

नवीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2021-22 में उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, पार्कों, धार्मिक स्थलों, पंचायतों और अस्पतालों में 30000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव है। छत के ऊपरी

भाग में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा और 13.2 मेगा वाट क्षमता को स्थापित करने का लक्ष्य 2021-22 में रखा गया है। इसी प्रकार, 2021-22 के दौरान सिंचाई एवं पेय जल के लिए 10000 सोलर वाटर पम्प लगाने का भी प्रस्ताव है। अगले राजकोषीय वर्ष के दौरान दो औद्योगिक जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों को भी पूरा करने का लक्ष्य है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 214 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

18. वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुपूरक अनुदान:

- (क) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1,01,428 करोड़ रुपए का मूल अनुदान था। 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान, सेवाओं से संबंधित व्यय को चुकाने और इस अवधि के दौरान अपेक्षित उद्देश्यों के लिए जम्मू एवं कश्मीर के समेकित निधि से संबंधित मांगों के अंतर्गत 12,002.06 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान निकाला जाएगा। यह मुख्यतः 11,025 करोड़ रुपए तक बिजली खरीद देयता को स्वीकृत करने के कारण व्यय, पंचायतों/यूएलबी/डीडीसी/बीडीसी चुनावों स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मशीनरी एवं उपकरण की खरीद के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आवर्धित आबंटन, भूमि क्षतिपूर्ति, कोविड-19 महामारी के कारण आवश्यक औषधि एवं औजार/मशीनरी तथा उपकरण के लिए अतिरिक्त आबंटन, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आवर्धित आबंटन, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के लिए आवर्धित आबंटन और मत्स्य पालन क्षेत्र की नीली क्रांति योजना के अंतर्गत आवर्धित आबंटन के कारण आवश्यक हो गया था।
- (ख) 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के समेकित निधि से 12,002.06 करोड़ रुपए के भुगतान को अधिकृत एवं विनियोजित करने के लिए अनुपूरक जम्मू एवं कश्मीर विनियोग विधेयक सं. (01) प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

19. जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश का वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान:

- (क) 2021-22 की कुल प्राप्ति 1,08,621 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें से 97,141 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति, 11,480 करोड़ रुपए ऋण के रूप में और 22,211 करोड़ रुपए अर्थोपाय अग्रिम के रूप में है। इसका स्वयं का राजस्व 24,485 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसके अलावा, 30,757 करोड़ रुपए जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश को केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया जाना है।
- (ख) इन प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, कुल 1,08,621 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान है। इसमें से पूँजीगत व्यय 39,817 करोड़ रुपए और राजस्व व्यय 68,804 करोड़ रुपए होगा।
- (ग) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के समेकित निधि से 1,30,832.24 करोड़ रुपए का भुगतान एवं विनियोग अधिकृत करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर विनियोग विधेयक सं. (02) प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

20. राजकोषीय संकेतक:

- (क) कर/जीडीपी अनुपात 8.10 प्रतिशत पर अनुमानित है जो पिछले वर्ष के 7.08 प्रतिशत से अधिक है।
- (ख) पिछले वर्ष का ऋण/जीडीपी अनुपात लगातार 48% है जो एफआरबीएम सीमा के भीतर है।
- (ग) वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी में वृद्धि 2,01,054 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% की वृद्धि दर्शाता है।
- 21.** अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस सदन को अनुपूरक बजट (01.04.2020 से 31.03.2021 के लिए), और जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के वर्ष 2021-22 के लिए बजट विचारार्थ प्रस्तुत करती हूँ।

**Supplementary Demand for Grants of the Union Territory of Jammu & Kashmir
(with Legislature) for 2020-2021 and Budget for 2021-2022**

Speech of
Nirmala Sitharaman
Minister of Finance

Mr. Speaker Sir,

1. Hon'ble Members of the august House are aware that after creation of Union Territory of Jammu and Kashmir by virtue of 'Jammu and Kashmir Re-organization Act, 2019" w.e.f. 31st October, 2019, the Union Territory of Jammu and Kashmir continues to be under the President's rule vide Gazette Notification S.O. 3937 (E), dated 31st October, 2019. The powers of the legislature of the Union Territory of J&K are exercised by or under the authority of the Parliament.
2. The creation of UT of J&K has ushered an era of hope and positivity. The people of J&K today look forward to a future free of corruption and separatism. We now have one nation, one constitution and one law. All 890 central laws have now become applicable to J&K. Unjust and discriminatory laws have been removed. 205 state laws have been repealed and 129 laws have been modified. All sections of people in J&K can look forward to justice and fairness. Rights of weaker sections like STs, other traditional forest dwellers, Scheduled Castes and Safai Karamcharis are now ensured by application of relevant Acts. Rights of children and senior citizens are now being ensured. In order to create a just and equitable society, reservation rules have been amended to extend benefits of reservation to left out categories like Pahari speaking people and economically weaker sections. OBC reservation benefits have been increased from 2% to 4% and income ceiling has been raised from Rs.4.50 lakh to Rs.8 lakhs. Sections of society which have been discriminated since ages such as displaced persons of PoJK and Chhamb, West Pakistani refugees and residents of border areas have been benefited under various schemes. Special attention is being paid to Kashmiri migrants.
3. Strengthening Gross-root Democracy:
One of the landmark decisions in recent times has been democratic decentralization in the spirit of 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. The Panchayat and Urban Local Bodies elections saw a turnout of over 74% and 4103 Sarpanchs and 28942 Panches were elected. The elections to Block Development Councils (BDCs) saw a voter turnout of 98.3% and 276 BDC Chairpersons were elected. The elections to District Development Councils (DDCs) saw a voter turnout of 51.7% and

saw election of 278 DDC members. The enthusiastic participation of people of J&K in DDC elections is indicative of positive changes that are beginning to take shape in J&K.

4. Transforming Governance:

- (a) A key feature since the creation of UT has been transformation of governance that is transparent, responsive and accountable. The Back to Village Programme which saw over 4000 officers spending two days including night halt in panchayats was an attempt to bring governance at the door steps. Rs.10 lakhs were provided to each panchayat under the programme for providing basic and other amenities in villages. Sports kits costing Rs.20,000 each were distributed in each Gram Panchayat under Back to Village Programme and 20,000 youths were identified for bank finance to start their own venture and Rs.241 crore have been disbursed to 15,000 youth.
- (b) A similar outreach programme was launched with respect to urban areas “My Town My Pride”. Under this programme at least 10 young men and women from each Municipality have been identified who have been provided opportunities to become entrepreneurs. These programmes have led to empowerment of people and creating a responsive administration. The unique Jan Abhiyan Initiative has helped in bringing immense accountability.
- (c) It is heartening to note that UT of J&K has achieved unprecedented level of transparency in financial management. The Budget Estimation, Allocation and Monitoring System (BEAMS) has been implemented by virtue of which the funds are now being released online and activity wise. The details of all the projects and related expenses have been put in the public domain through “EMPOWERMENT” web portal, part of BEAMS, to strengthen public participation in the developmental works and scrutiny. Geo-tagged photographs are essential for payments. For online billing, JK Payment System (JK Pay Sys) has been rolled across the Union territory. Through this, it has been made sure that no funds can be withdrawn in lieu of any work without the required administrative and technical approval or of any work where tendering has not been done. Whatever works are being done through the budget of the government, now every single penny is being accounted for and it is a matter of pride that the pace of development has accelerated due to this transparent mechanism. We are confident of making UT a model of development.
- (d) Our Government is taking care of the needs of the people during pandemic and has remained connected to people by regular conduct of Awami Mulaqat and Public Darbars. This programme of mass participation is going on continuously as Block Diwas and under this programme the government is reaching the door steps of people.

5. Accelerating Development:

- (a) Under Capex Budget of 2018-19, 8106 projects were completed. During 2019-20, 10500 projects were completed. This year 16000 projects i.e. double the number of 2018-19 are going to be completed. Not only this, there is significant reduction in cost of project completion as well despite the challenges of pandemic.

- (b) Speaker Sir, we are doing everything possible to fast-track development in J&K. The Udhampur—Srinagar—Baramulla Rail Link is expected to be completed by December, 2022. The 8.45 km long twin tube Qazigund Banihal tunnel is nearing completion. I would like to mention here that it has taken us 70 years to reach the capacity of 3500 MW power generation. But now by our efforts, MoU has been signed for generating further 3300 MW. J&K has achieved 100% household electrification under Saubhagya Scheme and expects 100% water connections under Jal Jeevan Mission by September, 2022. J&K UT is marching ahead with its ambition of road to every village. Since the creation of UT several languishing projects that were pending for decades are getting completed and over one thousand such projects are expected for completion before end of this year. J&K is truly moving on the path of “Sabka Saath Sabka Vikas Aur Sabka Vishwas”.

6. **Towards Managing Economy and Financial Inclusion:**

- (a) The steps taken under Atma Nirbhar Bharat Abhiyan have enabled J&K Government to deal with the pandemic and its economic fallout with great resilience. If we take SGST collections as an indicator of economic growth, it is heartening to note that SGST collections in J&K stands at Rs.453 crore over last six months as compared to Rs.393 crore last year over the same period. The average collection of stamp duty has also shown positive trend over the last six months. The return filing percentage in December, 2020 stands at 91% against national average of 86%. There is significant increase in the MST collection as well. It shows that economy is picking up. The tourism sector has also shown signs of revival. The latest footfall figures show that tourism sector has retained its hold over visitors from the country and abroad. Against 1,88,702 visitors to Jammu in October, 2020, 7,29,175 tourists visited in January, 2021. 2697 visited Kashmir in October, 2020 and 19102 travelled to Kashmir in January, 2021. Post relaxation in covid-19 pandemic, December, 2020 recorded the highest number of 13237 tourists in Kashmir, which is 39% of the total footfall in the entire year. Besides, 4,66,246 pilgrim tourists visited Jammu in the same period.
- (b) Speaker Sir, the Government has been taking a number of steps to infuse growth momentum in economy. The Government of J&K had announced special economic package of Rs.1,350 crore for relief and revival of business sector affected by long years of turmoil and COVID-19 pandemic. It includes Interest subvention of 5% in case of all borrowers for six months, 50% waiver of electricity and water charges, Customized 'Help Tourism' scheme by JK Bank for financial assistance to persons associated with the Tourism Sector, 80% subsidy amounting to Rs.1.80 crore for installation of the bio-digesters in the Houseboat and Payment of Rs.1,000 per month to Shikara-walas/Workers in the House boats/Tourist Guides/ Pithu-walas/ Dandi-walas/ Sledge-walas/Pony & Camel-walas for 9 months. Rs.8.17 crore has been disbursed to eligible beneficiaries out of J&K Relief Fund as part of business revival package during the current pandemic through DBT mode. The Government has given special focus to financial inclusion which has helped to improve liquidity in the market. So far, interest subvention of Rs.500 crore to around 4 lakh account holders as part of economic package has already been provided. Around 64,000 borrowers have been covered under GECL scheme for disbursement of about

Rs.1,773 crore. In addition 11,000 street vendors have been covered under PMSVANidhi scheme with an amount of Rs.11 crore. Under Kisan Credit Card scheme around 9.80 lakh beneficiaries have been covered with a credit outstanding of approximately Rs. 5,480 crore.

- (c) The economic package was well received alongwith Atma Nirbhar Bharat Abhiyan which has helped in creating a positive sentiment in the minds of people of UT of J&K.
- (d) Under Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Package 10.20 lakh beneficiaries have been covered under PM-Kisan component and an amount of around Rs. 204 crore have been credited directly into the accounts of beneficiaries. 38,000 beneficiaries have been covered under 2% interest subvention for Mudra (Shishu) Loans.

7. Accelerating Industrial Growth in UT of J&K:

- 7.1** The announcement of Central Sector Scheme for Industrial Development with approved outlay of Rs.28,400 crore has created immense hope for industrial development in J&K. The scheme incentivizes setting up of industries in relatively remote regions. While encouraging new investments, due support shall also be provided to the existing industries in J&K. Main purpose of the scheme is to generate employment which directly leads to the socio-economic development of the region. It also envisages development of Manufacturing as well as Service Sector Units in J&K. The main incentives are **Capital Investment Incentive, Capital Interest subvention, GST Linked Incentive and Working Capital Interest Incentive**. The scheme is being implemented with the vision that industry and service led development of J&K needs to be given a fresh thrust with emphasis on job creation of the order of 4.50 lakh people, skill development and sustainable development by attracting new investments and nurturing the existing ones. Investors from anywhere can set up their units even on private land without any undue restriction on transfer of ownership rights to such promoters. This step is a milestone in the Industrial Development in J&K.
- 7.2** With the objective of promoting investments in Jammu and Kashmir and prioritizing the focus areas for such investment, the Government of J&K has identified 14 (Fourteen) sectoral policies for attracting the investors. The sector specific policies shall be duly supported with an adequate land bank. Our Government has re-started preparations for a business summit aimed at drawing investments into the Union Territory, after the previous schedule for the meet was changed because of the Covid-19 pandemic. The Global Investors Summit is likely to be held in J&K during the next financial year. The summit had initially been planned for April, 2020 last year.
- 7.3** With effect from 01-01-2020 the Toll Tax at Lakhanpur entry point has been abolished with the objective of strengthening the integration of J&K with the other regions of the country in the spirit of "one nation one market".

8. Economic Growth:

Taking forward all initiatives, we expect to achieve GDP growth of 7.5% in 2021-22 which is our conservative estimate given the pandemic situation.

9. **Budget 2021-22:**

- 9.1 The budget 2021-22 for J&K shall focus on Good Governance aimed at maximum governance and minimum government, socio-economic development of the people, development of infrastructure across J&K and generation of employment which is our priority.
- 9.2 The budget for 2021-22 for J&K shall again cross Rs.1 lakh crore mark, an indicator of our commitment to make J&K a model of development. The total budget estimates for the fiscal is Rs.1,08,621 crore, of which developmental expenditure is of the order of Rs.39,817 crore.
- 9.3 The capital component of the budget has increased substantially. The expected revenue receipts are Rs.97,141 crore whereas revenue expenditure is expected to be Rs.68,804 crore thereby making available revenue surplus for capital expenditure to the tune of Rs.28,337 crore.
- 9.4 The Capital Receipts are projected at Rs.11,480 crore and Capital Expenditure is expected to the tune of Rs.39,817 crore. 37% of the earmarked Budget shall be spent on development and infrastructure projects.

10. **Direct Benefit Transfer:**

We have achieved good progress under DBT in respect of individual beneficiary schemes, besides Aadhar seeding. During the current financial year, Rs.2,070 crore have been disbursed through DBT to 88 Lakh beneficiaries. 100% saturation level is being achieved under Old Age Pension scheme and other beneficiary schemes through Direct Benefit Transfer during 2021-22. We intend to achieve 100% coverage under various scholarship schemes as well.

11. **Socio-Economic Development:**

11.1. **Health and wellness:**

- (a) J&K Government has taken due care of the well-being of the people during the Covid-19 pandemic. On 26th December, 2020 Hon'ble Prime Minister launched AB-PMJAY "SEHAT" Health Insurance Scheme in convergence with AB-PMJAY. Under this scheme all 21 lakh families of UT of J&K are covered for free medical treatment upto Rs 5 lakh per family. The scheme is not limited to government and private hospitals in Jammu and Kashmir only. Rather, treatment can be availed from thousands of hospitals empanelled under this scheme in the country. The extension of the coverage of Ayushman Bharat—PMJAY to all the residents was "historic" and indicative of resolve of Government regarding well-being of people of J&K.
- (b) 37 Oxygen Generation Plants in all Medical Colleges, Associated Hospitals and District Hospitals of UT of J&K are being established to cope up with additional requirement of medical oxygen due to COVID-19 pandemic at a cost of Rs.227.73 crore. Machinery & Equipments worth Rs.367.49 crore are being procured for health institutions through World Bank aided project. Two medi-cities are

being established. 500 bedded paediatric hospital at a cost of Rs.116.25 crore at Bemina, Srinagar shall be operationalized. Construction of 200 Bedded Additional Block at Lal Ded Hospital Srinagar at cost of Rs. 132.50 crore has already been undertaken. Construction of 120 Bedded Specialized Orthopedic Unit with 6 Bedded ICU at Bone and Joint Hospital Srinagar at a cost of Rs.88.94 crore is approved. Two New Medical Colleges at Udhampur and Handwara (District Kupwara) are going to be constructed at a cost of Rs.325 crore each. Two new AIIMS, one each in Jammu and Kashmir are also expected to come up in next financial year.

- (c) We are going to establish two Cancer Institutes at Srinagar & Jammu at a cost of Rs.120 crore each. "Institute of High Altitude Medicinal Plants" in J&K at Bhaderwah with an estimated cost of Rs.100 crore shall also be established.
- (d) Five Nursing Colleges are being established at Anantnag, Baramulla, Sopore, Gangyal and Kishtwar. 10 GNM Schools to the level of Nursing College are being up-graded at an estimated cost of Rs.6 crore per college. A Modern Drug Testing Laboratory is being set up at Kathua at a cost of Rs.34 crore.

For Health and Medical Education Sector, an allocation of about Rs.1,456 crore has been made for the year 2021-22 which is Rs.188 crore more than previous year's Budget Estimates 2020-21.

11.2 Agriculture and Horticulture Sector:

- (a) Jammu and Kashmir has got a historic opportunity to become a pioneer in the field of agriculture and horticulture. The government is making every effort to double the income of farmers by 2022 and special attention is being paid to both traditional agriculture and horticulture. With the collaboration of NAFED, Rs.1,700 crore will be invested to boost the production of apples, walnuts, cherries, exotic vegetable and other horticulture products over the next five years and three cold storage clusters will be setup at Kathua, North Kashmir and South Kashmir with an investment of Rs.500 crore. Our goal is to achieve high density plantation of horticulture crops on about 5500 hectares of land which will increase the income of farmer brothers by 3 to 4 times. 120 Hectare shall be expanded under High Density Plantation in 2021-22.
- (b) We will extend all possible support for skill development and employment generation opportunities for rural youth in horticulture and post harvest management. In 2021-22, Rs.74.55 crore is provisioned as additional subsidy/support for establishing C.A. Stores with a target to achieve 4 LMT capacity of CA storage in next three years.
- (c) During 2021-22, 7.50 lakh farmers shall be benefitted by distribution of one lakh quintal seeds with an investment of Rs.15.50 crore. 25000 farmers shall be benefitted by covering 87750 Hectare by providing infrastructure facilities like 2500 pump sets, 750 bore wells and construction

of many field channels with a provision of Rs.91.27 crore during 2021-22. 30000 farmers to be benefitted by providing farm machinery with a provision of Rs.65.81 crore in 2021-22. 25000 farmers shall be benefitted by establishment of two mandis with a provision of Rs.1 crore. 35000 farmers shall be trained for capacity building with a provision of Rs.26 crore.

- (d) To strengthen the farmers to meet the accreditation requirement of the Agriculture Universities through indicators like germplasm production, an amount of Rs.2.50 crore has been proposed.
- (e) The production of Saffron crop is expected to further increase with assured irrigation facility.
- (f) To augment the mulberry wealth under the proposed coverage of 700 Hectares, an amount of Rs.0.75 crore has been projected.
- (g) For development and production/distribution of quality silkworm seed along with the infrastructure support, Rs.7.25 crore are being provisioned in the next fiscal.
- (h) Export target for dry & fresh fruit for 2021-22 is expected to be 22.30 LMT (22 LMT for fresh fruit & 0.30 LMT for dry fruit).

For Agriculture and Horticulture Sectors, an allocation of about Rs.2,008 crore has been made for the year 2021-22 which is Rs.695 crore more than previous year's budget allocation.

11.3 Animal, Sheep Husbandry and Fisheries Sector:

- (a) In next year we are expecting to generate direct employment to 2000 people besides indirect employment to hundreds with implementation of Integrated Sheep Development Scheme by establishing 2000 units with induction of 27500 sheep/goats & additional production of 5 lakh Kgs of mutton. Introduction of 4000 additional rams/bucks to an existing strength of 5000 is expected to enhance carcass yield from 18 kg to 21 kg & wool yield from 2 kg to 2.5 kg. 20000 animals shall be inducted in milk pool with full implementation of Integrated Dairy Development scheme which will potentially improve employment in the dairy sector.
- (b) Mobile Veterinary Clinics shall be operationalized to ensure doorstep delivery of veterinary health care/breeding services to progressive livestock farmers.
- (c) Under J&K Poultry Policy, 2020 and Poultry Development programmes, poultry meat production is expected to increase from current 7.8 crore Kgs to 8.5 crore Kgs which has the potential for generation of employment opportunities for 30,000 people.
- (d) Government shall take adequate measures for enhancing the current fish production of 21 thousand MT by further 1000 MT through implementation of various schemes. Marketing

platform shall be strengthened with a provision of export of trout to other states of the country. New interventions like Re-circulatory Aquaculture systems & Biofloc technologies shall be introduced to boost fish productions in the UT. New hatcheries are to be established & existing ones strengthened with multiple tier systems to increase the seed production for the UT & for export as well.

For Animal, Sheep Husbandry and Fisheries Sectors, an allocation of about Rs.338 crore has been made for the year 2021-22 which is Rs.36 crore more than previous year's budget allocation.

11.4 Rural Economy:

- (a) Under the Pradhan Mantri Awas Yojana- Gramin during 2021-22 we are targeting completion of 1,17,419 houses in order to provide shelter in the form of pucca houses to the eligible rural families who are living in kutcha/dilapidated houses.
- (b) 39113 candidates shall be imparted training under Himayat (DDU-GKY) scheme and 20912 candidates are expected to be placed in different jobs during 2021-22.
- (c) 16000 Self Help Groups (SHGs) and 1600 number of Village Level Organisations shall be formed during 2021-22. 24866 SHGs shall be provided revolving fund and 46799 SHGs shall be provided community investment fund during 2021-22 under National Rural Livelihood Mission (NRLM).
- (d) On the development front we are expecting to complete 130 rural connectivity works during 2021-22.
- (e) To bring good governance at the doorsteps, training to the elected representatives is necessary. It is proposed to send 700 elected representatives on exposure cum training visits in other States. 276 BDC Chairpersons, all DDC Members, 4291 Sarpanches & 40000 Panches shall be provided training and 100 new panchayat ghars shall be constructed in 2021-22.
- (f) Mobile monitoring system for on-spot capturing of attendance of MGNREGA workers through mobile application shall be introduced.
- (g) Number of works to be taken-up for completion under MGNREGA is 0.60 lakh, which include 30% water conservation works and 30% individual beneficiary oriented works and 3.50 crore persondays are targeted to be generated.

For Rural Sector, an allocation of about Rs.4,817 crore has been made for the year 2021-22 which is Rs.342 crore more than the previous year's budget allocation.

11.5 Power Sector:

- (a) Under Atma Nirbhar Bharat Abhiyan, to bring power corporations of J&K to sustainable levels, our Government has allowed clearance of past liabilities of Rs.11025 crore. This measure is going to relieve department from the burden of liabilities and interest accruing from it and infuse new lease of life into its subsidiary companies constituted after unbundling of the Power Department.
- (b) Decks have been cleared for taking up new hydroelectric power projects like Kirthai-II (930MW), Sawalakote (1856 MW), Uri-I stage-II (240 MW) and Dulhasti stage-II (258MW) and modalities have been finalized for 850 MW new joint venture Ratle project.
- (c) Two Lakh smart meters are being installed under PMDP to be completed by June 2021 for all urban consumers to increase collection efficiency.
- (d) The transformer damage rate during current harsh winter conditions especially in Kashmir has drastically reduced. To further prevent damage of the transformers, Installation of Transformer Cut outs shall be extended to all feeders during 2021-22.
- (e) 24X7 e-customer care / call-center for grievance redressal shall also be established.
- (f) 22 projects shall be completed by October, 2022 for increasing transformation capacity at Grid level.
- (g) Solar plants shall be set up across the UT to promote use of renewable energy for which land has been identified in Pampore, Kalakote & Kawa for establishment of solar plants.
- (h) Optical Grounded Wire (OPGW) project for setting up efficient and reliable communication is under implementation by PGCIL under PMRP scheme which shall be accomplished to establish reliable/ efficient communication between 220 kV and 132 kV Grid Stations in the entire UT.

For Power Sector, an allocation of about Rs.2,728 crore has been made for the year 2021-22 which is Rs.119 crore more than the previous year's budget allocation.

11.6 Tourism and Culture:

- (a) Revival of Tourism sector post covid-19 pandemic is our utmost priority. Government shall make every effort for promotion of tourism by vibrant campaigning and holding of national and international events. New tourism destinations shall be explored through Public and Private Investment. Water based tourism activities shall be encouraged for promotion of adventure tourism. Promotion of Golf Tourism shall be taken at higher scale by holding national and international events. World class wayside amenities and facilities shall be provided besides

tourism related assets at all places shall be renovated and upgraded to increase and attract the high-end tourists.

- (b) We shall provide special attention for smooth conduct of Shri Amarnath Ji Yatra commencing in June/July this year to enable pilgrims to pay obeisance at the holy Cave with due facilities. We are also focussing on preservation and conservation of heritage sites. Last year I had announced development of three religious circuits including one Sufi circuit which are being developed by the J&K Government.
- (c) Government of J&K shall promote showcasing of its rich cultural heritage. In this regard the local film/cinema/theatre besides festival activities shall be promoted.

For Tourism and Culture sectors, an allocation of about Rs.786 crore has been made for the year 2021-22 which is Rs.509 crore more than previous year's budget allocation.

11.7 Jal Shakti Department:

I. PHE Sector:

(a) J&K is rich in water resources. We target 100% piped water connections to each and every rural household of the UT of J&K by September, 2022 under Jal Jeevan Mission (JJM). Two districts Srinagar and Ganderbal have already been covered and 9 districts are to be covered by March, 2022 and remaining 7 districts by September, 2022. Under this programme, 3.83 lakh water connections shall be provided during 2021-22 covering 19.65 lakh population. Besides, all the uncovered schools and anganwadi centres of the UT of J&K shall be provided water connections.

(b) 410 Water Supply Schemes are being completed during the financial year 2021-22.

II. Irrigation & Flood Control Sector:

(a) 57 Ongoing Minor Irrigation Schemes under AIBP-PMKSY shall be physically completed during 2021-22 and the Irrigation Potential of more than 0.19 lakh hectare shall be achieved.

(b) The devastating flood of 2014 still remains in our memories and a "Comprehensive Flood Management Plan of river Jhelum & its tributaries" is expected to get accelerated for achieving the target of enhancing the discharge capacity of river Jhelum to 60,000 cusecs from 41,000 cusecs at Sangam reference point and from 8700 cusecs to 17,000 cusecs at off-take of Padshahi Bagh, Srinagar. Work on Tawi Barrage (balance portion) and Ujh Multi-Purpose Project (UMPP) is also being started.

For Jal Shakti Department, an allocation of about Rs.6,346 crore has been made for the year 2021-22 which is Rs.5,102 crore more than the previous year's budget allocation.

11.8 Housing and Urban Development Sector:

- (a) Under **Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)**, 7 projects shall be completed in the next financial year which include Panjtirthi Multi Level Parking, Sewerage Treatment of 5 Nallahs of Tawi River at Jammu, Cycle track at Srinagar, Drainage at Trikuta Nagar, Multi Level Parking at Srinagar, Intelligent Traffic Management System (ITMS) phase-II, Srinagar & Water Supply scheme, Rangil.
- (b) Under Smart City Mission, 40 Projects of different sectors under convergence/PPP mode are expected to be completed during the next financial year. The main focus is to improve the quality of life of the people by way of providing WiFi facilities, Smart health centres, upgradation of historical markets, installation of vending machines, smart class rooms, electric vehicle (EV) charging stations, illumination of river banks, development of cycle tracks/hawker zones, development of parking and space under flyovers.
- (c) Under Swachh Bharat Mission (U) & Solid Waste Management, 16 new Sewage Treatment Plants (STPs) with 74 MLD capacity shall be installed which will cater nearly 2 lakh households. 25 Urban Local Bodies (ULBs) are targeted to achieve the status of ODF+ category.
- (d) 100% installation of LED Street Lights shall be ensured in all the 78 ULBs.
- (e) Our endeavour shall be to have 100% source segregation and Door to Door collection of waste. We will be establishing SWM Plant at Srinagar and Jammu for scientific disposal of about 850 MT of waste per day. We will establish decentralized processing units of waste management in 76 ULBs for scientific disposal of 690 MT of waste.
- (f) Rs.200 crore has been earmarked in 2021-22 for rejuvenation and restoration of 9 identified polluted river stretches by CPCB on the directions of NGT. Hull based bio-digesters shall be installed in house boats, aerators also shall be installed and de-weeding machines shall be procured.
- (g) Under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban), 25000 houses are likely to be completed in 2021-22. To identify genuine beneficiaries get the real benefits of the scheme 50,000 beneficiary houses shall be Geo-Tagged in 2021-22.

For Housing and Urban Development Sector, an allocation of about Rs.2,710 crore has been made for the year 2021-22 which is Rs.1,432 crore more than the previous year's budget allocation.

11.9 Education Sector—Building Human Capital:

- (a) In 2021-22, J&K targets to increase GER (Gross Enrollment Ratio) from 83.38, 72.77, 67.76 and 53.70 at Primary, Upper Primary, High School and Higher Secondary levels to 85.00, 74.00, 69.50 and 57.00, respectively. The Dropout rate at the high school level is targeted to further reduce from 17.12 to 15.00 by March, 2022 in J&K. 723 ICT labs are being established in equal number of Secondary and Senior Secondary Schools at a cost of Rs.46.27 crore. 38 Girls Hostels worth Rs.114.14 crore shall be completed. 40 Kasturba Gandhi Balika Vidhyalya (KGBV) buildings worth Rs.43.33 crore are also to be completed.
- (b) During 2021-22, 245 works shall be completed which include construction of model schools, additional classrooms, lavatory facilities, smart class rooms. 10 degree college buildings shall be completed at Banihal, Kupwara, Gool, Khilotran, Mahore, Kalakote, Hadipora, Singpora (Pattan), Villgam (Kupwara) and Paddar (Kishtwar) with construction of 108 additional classrooms in the existing degree colleges.
- (c) Modern science laboratory blocks shall be constructed in 10 colleges.
- (d) 1200 traditional classrooms shall be converted into IT enabled classrooms. Automation of libraries shall be undertaken in all the remaining degree colleges.
- (e) Student's skill centers shall be established in all the degree colleges. 10000 students shall be imparted training under Skill Enhancement Training (SET) Scheme. 382 Computer Aided Learning (CAL) centers shall be establishment in equal number of elementary schools at a cost of Rs.19.10 crore. 77 Vocational labs shall be established in equal number of High/Higher Secondary Schools at a cost of Rs.3.85 crore.

For School and Higher Education Sector, an allocation of about Rs.1,873 crore has been made for the year 2021-22 which is Rs.523 crore more than the previous year's budget allocation.

11.10 Road Connectivity:

- (a) J&K Government is contemplating to launch Online Monitoring System (JKPWDOMAS) w.e.f. 1st April, 2021 in which all the activity right from preparation of DPR to final bill payment shall be done in online mode.
- (b) Emphasis on quality check is mandatory to have better life and durability of the roads and bridges. Accordingly, emphasis is being laid on establishment of Quality Control Lab for every District.
- (c) National level consultants shall be engaged for development of mechanism for monitoring and roll-out of 3rd party inspection system.

- (d) Under PMGSY I & II, our efforts will be to cover road length of 4500 kms during 2021-22. We propose to connect 150 new habitations. J&K will be onboard for PMGSY III for which 1750 km road length is being sanctioned for up-gradation in 2021-22. Under PMGSY IV, Core Network for connecting habitations having 250+ persons as per census 2011 are targeted to ensure 100% road connectivity in J&K by 2021-22.
- (e) Overall 8000 kms of black-topping of roads is targeted to be achieved during 2021-22 under Cities & Towns/PMGSY/CRIF/NABARD.
- (f) 14 bridges are targeted to be completed in 2021-22 benefitting 2.85 lakh population.
- (g) Rs.100 crore has been already provided & further Rs.150 crore is being provided in 2021-22 for ensuring pothole free roads across J&K.

For Road and Bridges Sector, an allocation of about Rs.4,089 crore has been made for the year 2021-22 which is Rs.467 crore more than the previous year's budget allocation.

11.11 Industries and Commerce:

- (a) Besides new central sector scheme for industrial development announced by Hon'ble Prime Minister as already mentioned, a landmark decision, to give further boost to Industrial Sector in J&K, Rs.200 crore have been provisioned in 2021-22 for development of New Industrial Estates in UT. Government shall establish Trade Centres with outlay of Rs.50 crore. Rs.44.80 crore has been earmarked for development of new industrial estates at Mean Charkah (Samba), Karandi, Mearth Ghatti and Sahar Logate (Kathua) in Jammu Region.
- (b) Food Parks shall be established at Sangyote near Kud, Pahlipora (Lar) and Chewa (Bandipora) during 2021-22.
- (c) To ensure proper disposal of waste, three Common Effluent Treatment Plants (CETPs) are to be constructed in the existing industrial areas at an estimated cost of Rs.20.47 crore.
- (d) Two IT towers one each at Jammu and Srinagar capital cities are likely to be completed during 2021-22 at a cost of Rs.100 crore. Besides, rural BPOs at all district headquarters are expected to be established in 2021-22.
- (e) Under J&K Rural Employment Generation Programme involving Margin money of Rs.25 crore for 2021-22, employment opportunity to 7386 persons involving 1231 units is expected.
- (f) I am happy to inform this august house that 456 investment proposals/MOUs have been received involving an investment of Rs.23,000 crore in various sector in J&K where investors

have shown keen interest for the investments. Rs.50 crore has been provisioned for Organizing J&K Global Investors Summit including domestic/international road shows for promotion of investment in J&K.

- (g) 2000 Cooperatives/ Self Help Groups shall be covered under Credit Card Scheme benefiting directly/indirectly 12000 persons. 7% interest subvention shall be provided for availing loan upto Rs.2 lakh by artisans under Artisan Credit Card Scheme (ACC).

For Industries and Commerce Sector, an allocation of about Rs.648 crore has been made for the year 2021-22 which is Rs.291 crore more than the previous year's budget allocation.

12. Social Security Sector:

- (a) Construction of Bal Ashram, Nari Neketan Buildings and Half Way homes are being proposed in 2021-22.
- (b) Day care facilities in Anganwadi Centres shall be augmented and Common Application Software (CAS) for Integrated Child Development Scheme (ICDS) shall be rolled out to completely digitize the existing functioning of AWCs with real-time monitoring and record maintenance.
- (c) 100% coverage under 55 individual beneficiary schemes is being ensured. Special focus is being provided to border areas. 59% increase has been registered in beneficiaries under social security and pension schemes covering overall 742781 beneficiaries.
- (d) 100 % coverage of pre-matric and post-matric scholarship to Gujjar and Bakerwal students and ST students is being ensured with 100% disbursement through DBT mode. A 100% jump from 1091 to 2136 students under SC pre-matric scholarship and increase by 127% from 26032 to 59112 under post matric scholarship has been registered.
- (e) For economic upliftment of scheduled tribes, cluster tribal villages shall be developed with establishment of milk villages, libraries for Gujjars/Bakarwals. The hostel facilities for Gujjar, Bakarwal & ST students shall be created besides Ekalavya Model Residential Schools for ST students.

For Social Security Sector, an allocation of about Rs.174 crore has been made for the year 2021-22 which is Rs.59 crore more than the previous year's budget allocation.

13. Relief & Rehabilitation of Kashmiri Migrants:

I. Transit Accommodation:

Under PM Package, out of 6000 units, 1025 units of transit accommodation have already been completed. The work on 1488 units of transit accommodation is being undertaken in 2021-22, besides land has been identified for another 2444 units.

II. Employment:

Out of 6000 posts created for Kashmiri Migrants under PM Package, 3841 posts stand filled up and the remaining are being recruited.

III. Other Components:

The other components of the PM package like housing, employment, waiver on loans, cash assistance and free ration shall continue in 2021-22.

For above package, an allocation of about Rs.846 crore has been made for the year 2021-22.

14. Youth Empowerment, Employment and Entrepreneurship:

- (a) Two Centres for Invention, Innovation, Incubation and Training (CIITs) in collaboration with Tata Technologies are being established at Govt. polytechnic Jammu and Govt. Polytechnic Baramulla for upskilling of students of technical institutions in industry relevant courses like robotics, design engineering, electric vehicle maintenance and repair, internet of things, mechatronics and many more trades.
- (b) Youth engagement through “Mission Youth” is another major initiative of the Government of J&K for their upliftment and employment. A provision of Rs.200 crore has been made during 2021-22 for this initiative.
- (c) Government is ready to provide all possible financial support to youth for undertaking self-employment through various bank sponsored schemes and youth start up schemes besides self-employment through J&K Rural Employment Generation Programme and Prime Minister’s Employment Generation Programme.
- (d) Job Portal shall be created and job fairs are going to be organized for facilitating youth in getting jobs in private sector. The Overseas Employment Corporation to assist youth in obtaining jobs abroad shall also be revitalized.
- (e) 2000 unemployed youth shall be covered under Self Employment programme & Skill training shall be imparted to nearly 5000 youth, so as to make them employable in various trades/sectors.
- (f) Speaker Sir, I must mention here that 12379 Gazetted and Non-Gazetted vacancies besides 10000 Class IV vacancies have been identified for accelerated recruitment drive.

15. Sports Activities:

To keep youth engaged in sports activities, Government shall facilitate organising premier league in 4 disciplines viz football, kabbadi, volleyball and hockey with expected involvement of 8500

participants. We are committed to provide adequate opportunity to every willing youth to participate in sporting activity. People of J&K are showing keen interest in cricket. To bring cricket players under the ambit of proper coaching and acquaint them with better techniques MOU is being signed with Mr. Suresh Raina Academy for imparting training to budding cricketers of UT. Recently winter games under Khelo India programme were organized at "Gulmarg" which exhibited large scale participation of people from national and international level. Holding of winter games to be encouraged for inviting large scale participation, which will also boost tourism sector.

For youth empowerment, employment, entrepreneurship and sports activities, an allocation of about Rs.513 crore has been made for the year 2021-22 which is Rs.17 crore more than the previous year's budget allocation.

16. Environment:

A large scale plantation drive shall be launched to increase the green cover by planting nearly one crore trees during 2021-22. Wular lake is the Asia's largest fresh water lake. To protect this lake "Wular Lake Conservation and Management" action plan is under implementation for increasing the water holding capacity of the lake targeted for completion in 2021-22 at a cost of Rs.200 crore as a flood mitigation initiative. Further a provision of Rs.25 crore has been earmarked for construction of circular road around the Wular Lake to protect it from encroachment. State-of-Art Jumbo Zoo is being established at Jammu.

For Forest, Ecology and Environment Sector, an allocation of about Rs.218 crore has been made for the year 2021-22 which is Rs.3 crore more than the previous year's budget allocation.

17. Science, Technology and Information Technology:

To promote use of renewable energy, it is proposed to install 30000 solar street lights in suitable public places, roads, parks, religious places, panchayats and hospitals in 2021-22. Rooftop solar power system installation shall be encouraged and target for 2021-22 is to achieve installation of 13.2 MW capacity. Similarly, it is also proposed to install 10000 solar water pumps for irrigation and drinking water purposes during 2021-22. In next fiscal two Industrial Bio-technology parks are targeted to be completed.

For Science, Technology and Information Technology Sector, an allocation of about Rs.214 crore has been made for the year 2021-22.

18. Supplementary Grant for the current financial year 2020-21:

- (a) The original grant for the financial year 2020-21 was Rs.1,01,428 crore. During the course of year from 1st April, 2020 to 31st March, 2021 an amount of **Rs.12,002.06 crore** shall be withdrawn in excess of grant under the relevant Demands out of the Consolidated Fund of Jammu and Kashmir

to defray expenses on services and purposes required during the period. This had been largely necessitated due to expenses on account of clearance of power purchase liability to the extent of Rs.11,025 crore, expenditure related to Panchayats/ULBs/ DDCs/BDCs elections, World Bank aided scheme for procurement of machinery and equipments for health sector, increased allocation under PMGSY, land compensation, additional allocation for drugs and Instruments/ Machinery and Equipments necessitated due to Covid-19 pandemic, increased allocation under Jal Jeevan Mission (JJM), increased allocation under social security schemes and increased allocation under Blue Revolution Scheme of Fisheries Sector.

- (b) The Supplementary Jammu and Kashmir Appropriation Bill No (01) is proposed to be presented to authorize payment and appropriation of Rs.12,002.06 crore from and out of the Consolidated Fund of the UT of Jammu and Kashmir for the period w.e.f 1st April, 2020 to 31th March, 2021.

19. BUDGET ESTIMATES OF THE FINANCIAL YEAR 2021-22 FOR UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR:

- (a) The total receipts of 2021-22 are estimated at Rs.1,08,621 crore. Of these, Rs.97,141 crore are revenue receipts, Rs.11,480 crore are in the form of borrowings and Rs.22,211 crore are Ways & Means Advances. The own revenues are estimated to be Rs.24,485 crore. In addition to this, Rs.30,757 crore are to flow as central assistance to UT of J&K.
- (b) Given these receipts, the total expenditure is estimated to be Rs.1,08,621 crore. Of this, capital expenditure would be Rs.39,817 crore and revenue expenditure Rs.68,804 crore.
- (c) The Jammu and Kashmir Appropriation Bill No (02) is proposed to be presented to authorize payment and appropriation of **Rs.1,30,832.24 crore** from and out of the Consolidated Fund of the UT of Jammu and Kashmir for the period w.e.f 1st April, 2021 to 31th March, 2022.

20. Fiscal Indicators:

- (a) The tax/GDP ratio is projected at 8.10 percent for 2021-22 which is higher than the previous year of 7.08 percent.
- (b) Debt/GDP ratio for previous years has consistently remained below 48% which is within FRBM limits.
- (c) GDP growth for the year 2021-22 has been projected at Rs.2,01,054 crore which shows a growth of 7.5%.

21. Mr. Speaker Sir, with these words I present to the House the Supplementary Budget (for 1.4.2020 to 31.03.2021), and Budget for the year 2021-22 of Union Territory of Jammu & Kashmir for further consideration.